सूची में लगभग 2.41 लाख व्यक्ति दर्ज थे।

(ख) तेल उद्योग द्वारा मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में उपभोक्ताओं के नामांकन के अपने वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से नये एल पी जी कनेक्शन जारी करने का काम किया जाता है बशर्ते कि एल पी जी की उपलब्धता में वृद्धि हो।

(ग) तेल उद्योग आमतौर पर मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के उन कस्बों/शहरों को चरणबद्ध रूप से ले रहा है जिनकी जनसंख्या लगभग 20,000 या इससे अधिक (1981 की जनगणना के अनुसार) है, बशर्ते कि वहां एल पी जी के व्यवहार्य विपणन के लिए पर्याप्त तत्व मौजूद हों।

मध्य प्रदेश में कोयला भंडारों का दोहन

2438. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी सईदा खातून :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोयले के विपुल भण्डार के दोहन के लिए कोई दूरगामी योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि विनिर्दिष्ट की गई है तथा इसके द्वारा कितनेव्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ): (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए मध्य प्रदेश में कोयले के उत्पादन को अस्थायी तौर पर लगभग 83.90 मि० टन प्रक्षिप्त किया गया है। विद्यमान खानों और मंजूर परियोजनाओं के अंशदान के अलावा मध्य प्रदेश में 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान विकसित किए जाने के लिए कई नई परियोजनाओं को विनिर्दिष्ट भी किया है । आठवीं योजना की अवधि के लिए मध्य प्रदेश में विकसित किए जाने वाली विनिर्दिष्ट की गई नई परियोजनाओं के लिए राशि के निवेश की आवश्यकता लगभग 580 करोड़ रु० होगी । स्थानीय लोगों को उपलब्ध संभावित नियोजन की संख्या और उसके स्वरूप की स्थिति विशिष्ट परियोजनाओं की वास्तविक आवश्यकता पर निर्भर करेगी ।

नई परियोजनाओं में अकुशल और अर्ध-कुशल श्रेणियों में उपलब्ध होने वाले रोजगारों को तरजीह आधार पर भूमि-वंचित विस्थापित परिवारों को दिया जाता है।

कोरबा विद्युत संयंत्र से राज्यों द्वारा किये गये विद्युत उपयोग का औसत

2439. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी सईदा खातून :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरबा विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत का उपयोग किन-किन राज्यों द्वारा तथा किस अनुपात से किया जा रहा है ; और

(ख) इसमें से मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) पश्चिमी क्षेत्र में अप्रैल-जून, 1989 की अवधि के दौरान कोरबा

विंध्याचल सु० ता० वि० केन्द्र से विभिन्न राज्यों की पात्रता की तुलना में वास्तविक आहरण निम्न प्रकार था :

राज्य	पात्रता (मि० यू०)	वास्तविक आहरण (मि० यू०)	वास्तविक आहरण/पात्रता का %
गुजरात	593.3	553.2	93.24
मध्य प्रदेश	934.3	1168.2	125.05
महाराष्ट्र	760.8	722.9	95.02
गोवा	216.4	60.5	27.96

बिजली की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव

2440. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी सईदा खातून :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिजली की कमी के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वर्षवार अनुमानतः कितनी वार्षिक हानि हुई है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान किन-किन राज्यों में वर्षवार सर्वाधिक बिजली की कमी रही है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) बिजली की कमी के कारण उत्पादन की हानि के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं । डी० जी० टी० डी० के अनुसार, सीमेंट, कागज, औद्योगिक गैस, इस्पात ढलाई इत्यादि का निर्माण करने वाले कुछ एककों में उत्पादन पर असर पड़ा है । तथापि, कुल मिलाकर देश में औद्योगिक विकास की दरें 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान क्रमशः 9.1 प्रतिशत, 7.3 प्रतिशत और 8.8 प्रतिशत थी ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन राज्यों में बिजली की कटौती हुई है उनके नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । **(नीचे देखिए)** ।

विवरण

वे राज्य/संघशासित क्षेत्र जिनमें 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान बिजली की कटौती की गई/प्रतिबन्ध लगाए गए

1988-89	1987-88	1986-87
1. हरियाणा	1. हरियाणा	1. हरियाणा
2. चण्डीगढ़	2. चण्डीगढ़	2. चण्डीगढ़

1	2	3
3. हिमाचल प्रदेश	3. जम्मू और कश्मीर	3. हिमाचल प्रदेश
4. जम्मू और कश्मीर	4. हिमाचल प्रदेश	4. जम्मू और कश्मीर
5. पंजाब	5. पंजाब	5. पंजाब
6. राजस्थान	6. राजस्थान	6. राजस्थान
7. उत्तर प्रदेश	7. उत्तर प्रदेश	7. उत्तर प्रदेश
8. गुजरात	8. गुजरात	8. गुजरात
9. महाराष्ट्र	9. महाराष्ट्र	9. मध्य प्रदेश
10. मध्य प्रदेश	10. आन्ध्र प्रदेश	10. महाराष्ट्र
11. आन्ध्र प्रदेश	11. कर्नाटक	11. कर्नाटक
12. कर्नाटक	12. तमिलनाडु	12. तमिलनाडु
13. तमिलनाडु	13. पांडेचेरी	13. पांडिचेरी
14. केरल	14. प० बंगाल	14. प० बंगाल
15. पाण्डिचेरी	15. उड़ीसा	15. उड़ीसा
16. उड़ीसा		

स्रोत : देश में बिजली की आपूर्ति की स्थिति (सी० ई० ए०)

Assembling of Maruti vehicles with CKD and SKD kits from Japan -

2441. SHRI VIRENDRA VERMA *I*
SHRI ISH DUTT YADAV ;

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the total number of kits, both CKD and SKD, received by M/s. Maruti Udyog Ltd. from their principles in Japan since its inception upto the 31st March, 1989;

(b) what is the number of vehicles that were expected to be assembled. . with the material contained in the kits and bow many vehicles were actually assembled; and

(c) what are the reasons for the shortfall, if any ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO) : (a) The total number of CKD/SKD kits received by Maruti Udyog Ltd. from Suzuki Motor Company, Japan since its inception upto 31-3-1989 was 3,62,736.

(b) The number of vehicles expected to be assembled with the material contained in the kits till 31-3-1989 was 3,47,572. The number of vehicles actually assembled till 31-3-89 was 3,53,109.

(c) Does not arise.

Losses suffered by M/s. Maruti Udyog Ltd. due to pilferage of spare parts.

2442. SHRI VIRENDRA VERMA: SHRI ISH DUTT YADAV:.

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the estimated annual loss suffered by M/s. Maruti Udyog Limited due to pilferage of spare parts etc. during the last three years, yearwise till date stating the percentage of rise in the losses on this account; and

(b) what efforts have been made to plug the loopholes and to identify the employees, if any, involved in the pilferage of spare parts ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO) : (a) There has been no loss suffered by Maruti Udyog Limited during the last three years due to pilferage of spare-parts.

(b) During the last three years, 3 attempts to pilfer spare-parts were foiled and necessary action such as lodging of FIR's was taken. For preventing pilferage of spare-parts the following measures have also been taken, in addition to the regular effort towards development of systems :—

1. Sealing ofthe spare-parts warehouse after working hours
2. Loading of all material in the presence of security personnel.
3. Random checking of out-going consignment at the gate.
4. A strong room is being cons--tructedto store small size and high value components with proper system of receipt and issue.
5. Fencing ofthe compiste spare-parts warehouse area.

B.I.C.P. recommendations on the prices of Dexasnethasone

2443. SHRI SANTOSH KU MAR. SAHU : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what are the reasons for the delay in notifying the prices of Dexamethasone and its formulations;

(b) whether it is a fact that the prices notified by his Ministry are based on the recommendations of BICP ;

(c) if so, when were the recommendations received and what price was recommended for each ;

(d) whether it is also a fact that his Ministry were aware that the company was enjoying mark-up of more than 100 per cent and upto 207 percent as against their entitlement of 60 per cent and 100 per cent under DPCO, 1979 and;

(e) if so, what corrective steps are being taken in the matter ? .

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. NAMGYAL) :.(a) to (c) and (e) The recommendations of the **BICP** regarding prices of Dexamethasone formulations were received in this Department on 6th March, **1989.** While the prices of non-leader